[श्री हरीश कुमार गंगवार]

है, क्योंकि टेलिविजन में चित्र आते ही नहीं और यदि थोड़ा बहुत आते भी हैं तो अत्यंत अस्पष्ट होते हैं । अत: नागरिक परेशान हैं ।

यही नहीं पास पड़ौस के रोहिलखंड कमिशनरी के अन्य ज़िलों बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत की भी यही स्थिति है, वहां भी टेलिविजन सेट में चित्र अत्यंत ही धूमिल आते हैं और इस प्रकार इन सभी ज़िलों नागरिक संचार की इस महत्वपूर्ण सुविधा के लाभों से वंचित रह रहे हैं तथा टेलिविजन सैट्स में उनके द्वारा किया गया व्यय तथा दी जाने वाली लाइसेंस फीस धूल में मिल गए हैं ।

अत: संचार मंत्रालय एवं सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि वह बरेली में एक टेलिविजन केन्द्र अविलम्ब खोलने की व्यवस्था करे और तब तक एसी व्यवस्था करे कि बरेली तथा पड़ौस के उपरोक्त नगरों में टेलिविजन सैट्स में चित्र स्पष्ट रूप से उभर सकें और उनका पूर्ण उपयोग हो सके ।

(vii) REHABILITATION OF REFUGEES FROM SIND WHO CAME TO INDIA DURING 1971 INDO-PAK CONFLICT.

13 hrs.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota): As a result of 1971 Indo-Pak conflict, about 60,000 refugees migrated to India from occupied territory of Sind. Most of these refugees had, after some time, gone over to refugee camps set up by the Government. Some of these refugees, however, after getting themselves registered with the concerned Government authorities, went to meet their relatives who had migrated to India in 1947, not knowing that they will be denied the rehabilitation benefits if they did not settle down in the refugee camps.

Faced with the problem of livelihood, they started working as agricultural labour, cart-pulling and other forms of labour; a few started business also. Majority of them have not been able to earn adequate living.

They approached the Government of India for their rehabilitation. They were told that the matter would be considered after the refugees in the camps are settled. Sir, those who want to make their own efforts for earning are depending solely on government doles in camps.

According to a letter of the Ministry of Supply and Rehabilitation (Dept. of Rehabilitation) addressed to the President, Sindhi Sharanarthi Samasya Navaran Samiti, Jaipur, the refugees who were granted Indian citizenship should be granted rehabilitation benefits.

After meeting the State and Central Government authorities, it appeared that the rehabilitation benefits are not being extended to the persons living outside the camps.

It is surprising that 101 families who came to India from Sind one year after war managed to settle in camps set up in 1972. When the real facts about them came to the knowledge of the Government, they were thrown out of the camps but now, surprisingly, they are being given the rehabilitation benefits.

I request the Minister of Supply and Rehabilitation to make a statement in this regard.

13.02 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS, 1982-83— *Contd.*

MINISTRY OF COMMERCE—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Commerce. Shri Chandradeo Prasad Verma was on his legs.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष माननीय वाणिज्य मंत्री ने जो एक वस्त्र नीति की घोषणा संसद में ही, दोनों सदनों में की थी, उसके संबंध में क्या काम हुआ है अभी तक । एक वर्ष में क्या उसके बारे में प्रगति हुई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हालांकि इसके पहले उप-मंत्री महोदय ने इसके ऊपर भाषण किया है लेकिन उसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा । बहुत विस्तार में वह नीति है, मैं उस सब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन उसमें कुछ मुद्दों की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । घोषणा के मुख्य मुद्दों में से कुछ ये हैं । छोटे बुनकरों तथा इनसे संबंधित अन्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उसका विकास करना, कमजोर वर्गों के लिए सस्ते कपड़े का वितरण करना, मानव निर्मित रेशे तथा यार्न में वृद्धि करना, हथकरघा क्षेत्र में बेकार पड़े करघों को पुन: चालू करना, अधिक उत्पादन के लिए आधुनिकीकरण करना, उचित दामों पर यार्न देना, हथकरघों द्वारा पालियेस्टर तथा गैर-सूती वस्त्रों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण पर कड़ा नियन्त्रण रखना क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में बड़ा गौलमाल होता है और गरीब व्यक्तियों को वह मिल नहीं पाता । उचित कीमत पर रूई उपलब्ध कराना, आदि । ये सब कार्य सरकार द्वारा हो रहे हैं । जो नीति घोषित हुई थी, क्या सरकार उस पर चल रही है । स्पष्ट है कि इस नीति के अनुसार काम नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है ।

भारत में लगभग 35 लाख हथ-करघे हैं । मेरे पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और मैं यह समझता हूं कि इस के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है । हथकरघा चलाना बहुत कठिन काम है । रातदिन यदि हथकरघे में पूरा परिवार भी लगा हुआ है, तब भी उसको खाने भर की मजदूरी नहीं मिल पाती है । इसलिए इसमें कुछ विकास करने की आवश्यकता है । जो इस का विकास नहीं हो रहा है, उसी कारण इसमें लोगों को लाभ भी नहीं मिल रहा है इसलिए और नई पीढ़ी के लोग इसमें आ नहीं रहे हैं और यह उद्योग टप्प पड़ता चला जा रहा है । इन लोगों को जो सहायता दी जा रही है, अफसर और बिचोलिए करीब-करीब वह सारा पैसा खा जाते हैं और इन लोगों तक पहुंचते-पहुंचते वह सारी सहायता समाप्त हो जाती है । इसलिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । और वस्त्र उद्योग के लिए एक ओर स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है । जो लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग इस धंधे में लगे हुए हैं उन लोगों को स्पष्ट रूप में

*Moved with the recommendation of the President.